

संस्कारधानी से प्रकाशित मध्यभारत व  
छत्तीसगढ़ अंचल का सर्वप्रसारित  
लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्र

भारत सरकार व  
छत्तीसगढ़ शासन से  
विज्ञापन के लिए अधिकृत

वर्ष- 43 अंक - 248

दैनिक प्रातः संस्करण

"यो आत्मनं वेति, सर्वं स वेति।"

आर.एन.आई.नं. 58841/93

डाक पंजीयन छ.ग./दुर्ग/14/2024-26

# दैनिक

सम्पादक - दीपक कुमार बुद्धदेव

राजनांदगांव, गुरुवार 25 जुलाई 2024

पृष्ठ - 8 मूल्य - 4.00 रुपए

**धमाका**  
ई रिक्षा के द्वेष में आलफाइन लाए हैं...  
SINE WAYE TECHNOLOGY से  
प्रति चार्जिंग 200 KM चलने वाला  
भारत का पहला ई-रिक्षा  
7 वर्षों से ई रिक्षा बैटरी, स्पेयर्स पार्ट्स  
एवं बेहतरीन गुणवत्ता के लिए.....  
गणेश ट्रेडिंग, गमाधीन मार्ग, राजनांदगांव, 70004 70280  
★ नंदई भोजन रोड 7999898741 \* खेरांग (धमधा रोड) 9425500166

## आम बजट में भेदभाव का आदेष लगाते हुए विषयक ने दाज्यत्यमा से किया बहिर्भावन

नयी दिल्ली। कांग्रेस के नेतृत्व में विषयकी दलों ने बुधवार को आम बजट 2024-25 में विवाद और अधिकारी प्रश्नों को छोड़कर अन्य राज्यों की अनदेखी करने के आरोप लगाते हुए राज्यसभा से बहिर्भावन किया।

विषयकी निर्मला सीतारमण ने विषयक के अन्य राज्यों को 'बेतुवा' करार देते हुए सिसे खारिज कर दिया और कहा कि बजट भाषण में राज्यों का नाम न लेने का अर्थ वह नहीं है कि उन्हें नजरअंदाज किया गया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा पूर्व में पेश किए गए बजट में भी सभी राज्यों का कभी उल्लेख नहीं रहा। सभापति नारायण धननंद द्वारा नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस खारिज करने के बाद विषयक के नेता मिलिकार्पुर खण्डों ने बवाल का जिक्र करते हुए कहा, "इसमें किसी भी राज्य को कुछ नहीं मिला। सबकी थाली खाली और दो की थाली में पकोड़े और जलेंगी।"

उन्होंने दबाव किया कि बजट में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और ओडिशा राज्यों को कुछ नहीं मिला।

उन्होंने कहा, "मैंने ऐसा बजट कभी नहीं देखा। यह सिफर किसी को खुश करने के लिए जूझता है। हम इसकी निंदा करते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 'ईडीजा' गढ़वाल के दल इसकी निंदा करते हैं।" खण्डों ने आरोप लगाया कि जिन क्षेत्रों में विषयकी पार्टी चुनकर आई है या जहां जनता ने सत्तारूढ़ पार्टी को नकर दिया है, उन



क्षेत्रों को बजट में नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने प्रश्न उठाया कि आम बजट में संतुलन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में विषयकी दलों ने सदस्य संघरण कर गया।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भजप) हाल ही में संघरण आम चुनाव में बहुत द्वासाल नहीं कर सकी थी। विहार की जनता दल (भूमिकट) और आम प्रदेश की तेलुगु देश पार्टी (तेपा) के समर्थन पर यह सरकार टिकी है। दोनों दल लंबे समय से अपने-अपने राज्यों के लिए विषयकी दलों को मांग करते हैं। सीतारमण ने मंगलवार को पेश बजट में ऑफिशियल देश के लिए 60,000 करोड़ रुपये की घोषणा की

और दक्षिणी राज्य के लिए बहुशक्ती एजेंसियों से 15,000 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करने के लिए संसद का वादा किया। खण्डों के अपरोपें का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि बजट भाषण में अक्सर हर राज्य का नाम लेना संभव नहीं होता है तोकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यों को नजरअंदाज किया गया है।

सीतारमण ने कहा कि उन्होंने बजट पेश करने के दौरान महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया तो लेकिन हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 76,000 करोड़ रुपये की लागत वाली विधायक बंदरगाह परियोजना (महाराष्ट्र) को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि वह एक सकृती है जिनमें विषयकी दलों के मिलने हैं।

उन्होंने कहा, "यदि भाषण में किसी राज्य का नाम नहीं है तो क्या इसका मतलब यह है कि भारत सरकार की कार्यक्रम, विद्युत बैंक, एशियार्थ विकास बैंक, एआईआईबी और इस तरह के संस्थानों ने मिलने वाली राज्यों में नहीं जाती है? वे एक तथा कार्यक्रम के अनुसार जारी रहते हैं।" यह मिस्री के लिए कि सरकार के व्यापक विवरण में दम्भवर राज्यों के आवर्टन का जिक्र होता है। उन्होंने विषयकी दलों पर आरोप लगाया कि वे ऐसा विश्वास गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सीतारमण ने मंगलवार को कहा, "विषयक के नेता ने जो आरोप लगाए हैं, (शेष पृष्ठ 6 पर.)

## बिहार में एंटी पेपर लीक विल पास- नकल और परीक्षा में धांधली करने वालों को 10 साल की सजा, एक करोड़ तक जुर्माना

पटना। बिहार में नकल करने वालों होती ही राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न की अब खेल नहीं। नीतीश सरकार पेपर लीक और धांधली रोकने के लिए एंटी पेपर लीक करने वालों को 10 साल की अवधि और एक

सख्त कानून ला रही है। कानून के तहत पेपर लीक करने वालों को जारी करने की अपील आज एक

करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 24 जुलाई यारी आज बिहार की विधानसभा में पेपर लीक करने वालों को जारी करने के लिए ब्लैक लिस्टिंग किया जाएगा।

### एक कानून में द्वासा वात का भी प्राप्तवान

एन नियम के प्राप्तवान, पेपर लीक मामले की जारी द्वासपी ईके के अधिकारी को मुताबिक, अब पेपर लीक करने वालों को जारी करने के लिए ब्लैक लिस्टिंग किया जाएगा।

नए नियम के प्राप्तवान की जारी द्वासपी ईके के अधिकारी

## भाजपा ने बजट के विरोध को बताया कांग्रेस की बौखलाहट, कहा- एनडीए को कमजूर करने की कोशिश हुई नाकाम

नई दिल्ली। कांग्रेस विषयकी दलों द्वारा बजट के विरोध को भाजपा ने बौखलाहट का नीतीजा करार दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रक्रिया जीवीएल नारायण सह के अनुसार 2024-25 के बजट का सभी वार्षों ने ख्वागत किया है और इसमें शिक्षा और रोजगार का विशेष ध्यान रखा गया है।

बिहार और अंध्रप्रदेश को विशेष सहायता को प्रविधान को ख्वागत होते हुए उन्होंने कहा कि इसकी साथी सरकार 2014 के बाद सभी बजट में छिड़े क्षेत्रों के विकास पर जोर देती रही है और यह सहायता भी उसी का परिणाम है। भाजपा ने कांग्रेस के दर्जे में युवाओं को विशेष राज्य के दर्जे में मुद्रा उत्तराधिकार जदू और ईटीडीपी की दर्जे में शामिल होनी उसे चार साल के लिए ब्लैक लिस्टिंग किया जाएगा।

एन नियम के प्राप्तवान की जारी द्वासपी ईके के अधिकारी

संघरण विषयकी दलों पर आरोप देश के लिए विशेष सहायता दी गई है। इसके साथ ही पूर्वदिव्य योजना के दूरत देश के पूर्व पूर्वी इलाके के नेता बौखलाहट के विरोध कर रहे हैं।

### बजट में संतुलित विकास पर जर

भाजपा प्रवक्ता ने साफ किया कि 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट में सिफर विवर और अंध्रप्रदेश की विशेष सहायता के बजट नहीं है, क्योंकि सभी राज्यों के संतुलित विकास पर जरूर देने का वायदा किया गया था। अब वही मोदी सरकार द्वारा राज्यानी के निर्माण को लिए विशेष सहायता को प्रविधान को विशेष राज्य के दर्जे में देखते हुए कि इसमें विषयकी दलों के अनुसार जारी रहते हैं। अंध्रप्रदेश की विशेष राज्य का दर्जा नहीं है और यह विषयकी दलों के अनुसार जारी रहते हैं।

संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए ही इन दोनों राज्यों के लिए विशेष सहायता दी गई है। इसके साथ ही पूर्वदिव्य योजना के दूरत देश के पूर्व पूर्वी इलाके के माफ नहीं करेगी।

## जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी : भाजपा

उन्होंने कांग्रेस के चुनावी विशेषान्वयन को देखते हुए कि इसमें सिफर विषयकी दलों को विशेष सहायता के बजट नहीं है, क्योंकि विशेष सहायता के बजट नहीं है, विषयकी दलों के बजट नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के विशेष सहायता के बजट के लिए विशेष सहायता को देखते हुए कि इसमें सिफर विषयकी दलों के बजट नहीं है, विषयकी दलों के बजट नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के विशेष सहायता के बजट के लिए विशेष सहायता को देखते हुए कि इसमें सिफर विषयकी दलों के बजट नहीं है, विषयकी दलों के बजट नहीं है।

विकास पर ध्यान दिया गया है, जिसमें पूर्वदिव्य विवर, विशेष सहायता की जांच करने की माफ नहीं करेगी।

विकास के प्रधान पर ध्यान दिया गया है, जिसमें पूर्वदिव्य विवर, विशेष सहायता की जांच करने की माफ नहीं करेगी।

आयोजित सभा में पूर्व

विशेष सहायता की जांच करने की माफ नहीं करेगी।

विशेष सहायता की जांच करने की माफ नहीं करेगी।

विशेष सहायता की जांच करने की माफ नहीं करेगी।













